भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2892
जिसका उत्तर मंगलवार 13 मार्च, 2018 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु बैटरियां

2892. एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु बैटरियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किसी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या किसी निजी कंपनी ने बैटरियों के विनिर्माण में रुचि दिखाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मेन्यूफेक्चरर्स (एसआईएएम) ने सूचित किया है कि लिथियम आयन सेलों का आयात करके देश में पहले से ही बैटरी पैक की असेंबली/विनिर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) की संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम (एमएसआईपीएस) नामक एक योजना है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लिथियम जैसी उन्नत स्टोरेज बैटरियों को शामिल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक/टेलिकॉम उत्पादों के विनिर्माण हेतु सहायता शामिल है।

(ग): सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मेन्यूफेक्चरर्स (एसआईएएम) ने आगे सूचित किया है कि सुजूकी और डेन्सो के साथ तोशिबा ने पहले ही गुजरात में बैटरी और सेल विनिर्माण यूनिट की स्थापना आरंभ कर दी है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग ₹1200 करोड़ है।

*****